भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4034
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

मंगलौर में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन सुविधा

†4034. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ओएनजीसी ने मंगलौर में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता, निवेश आवंटन और इसके पूरा होने की संभावित समय-सीमा सहित परियोजना के स्तर का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ओएनजीसी का हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में निवेश इसके शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों का एक भाग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सुविधा ऊर्जा परिवर्तन में योगदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना वर्ष 2030 और 2038 तक भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप हो, क्या विशिष्ट कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार की मंगलौर में मौजूदा शोधनशालाओं के आस-पास डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को सुगम बनाने की कोई योजनाएं हैं जिससे इस क्षेत्र को पेट्रोरसायन और ऊर्जा केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता का लाभ उठाया जा सके; और
- (ङ.) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं, निधि आवंटनों और कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिक्स लिमिटेड के कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त मैंगलोर में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए व्यावहार्यता-पर्व अध्ययन किया है। निवेश के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ओएनजीसी, अन्य बातों के साथ-साथ हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित विभिन्न उपायों को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2038 तक निवल शून्य स्थिति प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपने प्रचालनों को निरंतर बढ़ा रहा है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन दस्तावेज के अनुसार, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन सामान्यतया ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन की तुलना में प्रति किलोग्राम उत्पादित हाइड्रोजन से लगभग 10 किलोग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करता है।

(घ) और (ङ): रसायन एवं पेटोरसायन विभाग ने जनवरी, 2022 में कल 62.78 करोड़ रुपए की परियोजना लागत, जिसमें 31.38 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान शामिल है, के साथ मैंगलूरु, कर्नाटक में एक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का अनुमोदन किया है और वर्तमान में यह कार्यान्वयन के चरण में है।